स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग). जी नहीं। सरकार को ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं। इस मामले में और आगे पूछताछ की जाएगी।

Allotment of Plot to E. P. E. Organisation for Construction of Office

2156. SHRI MANOHAR LAL: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the plot allotted to the E.P.F. Organisation near Connaught Place was cancelled which caused a loss of Rs. 3.5 lakhs to this Social Security Department of the poor workers;

(b) whether allotment of the plot was cancelled with the intention to allot the same to the Delhi Pradesh Congress Committee and he had assured in the last session of the Parliament to inquire whether the allotment was cancelled to allot it to somebody else; and

(c) what is the progress in the matter and how much time Government will take to allot the same plot or another plot to the Employees Provident Funds Organisations?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) E.P.F. authorities have reported that as a result of the cancellation of the plot allotted to the E.P.F. Organisation at Barakhamba Lane, the Organisation has lost about Rs. 4,06,000.00 as interest and other charges such as ground rent, expenditure on preparation of building plans by the Achitects and cost of demolition of old Bangalows on the plot.

(b) The allotment made to the Employees Provident Fund Organisation in Barakhamba Road area was cancelled as, according to the recommendations of the New Delhi Redevelopment Advisory Committee, the area was to be developed in an integrated manner. It was decided to allot the entire area to the New Delhi Municipal Committee for development. It was not intended to be allotted to the Delhi Pradesh Congress Committee.

(c) Allotment of a suitable plot is being pursued with the Ministry of Works and Housing.

राजस्थान में रेफरल अस्पताल खोलना

2157. **श्री हीरा भाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की योजना के अनुसार राजस्थान को राज्य में रेफरल अस्पताल खोलने का कोटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां कितने रेफरल अस्पताल खोले जाएंगे और उक्त अस्पताल किन-किन जिलों और स्थानों पर खोले जाएंगे ;

(ग) क्या जिन क्षेत्रों में रेफरल अस्पताल खोले जाएंगे उन क्षेत्रों के लोगों से योगदान के रूप में धनराशि लेने की शर्त रखी गई है, और यदि हां तो कितनी राशि लेने की शर्त रखी गई है; और

(घ) क्या पिछड़े क्षेत्र में उपर्युक्त अस्पताल नहीं खोले जाएंगे क्योंकि वहां के निवासी उक्त शर्त पूरी करने में असमर्थ हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख). यहां ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत राज्यों में खोले जाने वाले रेफरल अस्पतालों का कोटा नियत किया गया हो।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रैफरल सेवाएं अपर्याप्त हैं यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक का दर्जा बढ़ा कर 30 पलंगों वाला ग्रामीण अस्पताल बना दिया जाए । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चिकित्सा, सर्जरी संज्ञाहीनता, प्रसूति तथा स्त्री रोग सम्बन्धी सामान्य एवं विशेषज्ञ सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये 1293 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर 30 पलंगों वाले ग्रामीण अस्पताल बनाने का विचार था । राजस्थान सरकार भी ऊपर दिये गये पैटर्न तथा प्रत्येक वार्षिक प्लान के लिये उपलब्ध साधनों के अनुसार रेफरल अस्पतालों का विकास करेगी ।

(ग) और (घ). ऐसे रैफरल अस्पतालों को खोलने के लिये जनता से चन्दा एकत्र करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । अतः लोगों की माली हालत का हिसाब न रखते हुए ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे ।

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्ति

2158. **श्री गंगा भक्त सिंह :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग बेरोजगार व्यक्तियों की नवीनतम संख्या क्या है; और

(ख) बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि कोई समयबद्ध कार्यक्रम है तो वह क्या है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने अपने 27 वें बार (1972–73) में ऐसे व्यक्तियों की संख्या का अनुमान दिया है जो सामान्यतः रोजगार चाहते हैं तथा रोजगार के लिए उपलब्ध होते हैं (तिथि वार बेरोजगार) यह संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 18.33 लाख तथा शहरी क्षेत्रों में 20.35 लाख दी गई हैं ।

(ख) सरकार ने पहले ही यह निर्णय किया है कि विकास योजना के अगले चरण का मुख्य उद्देश्य लगभग दस वर्षों में बेरोजगारी तथा काफी हद तक अल्प रोजगारी को समाप्त करना होगा । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार का जिन कार्यवाहियों को करने का प्रस्ताव है उनका ब्यौरा अगली योजना में दिए जाने की सम्भावना है ।

चीन के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत

2159. **श्री भारत भूषण :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में चीन के व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल की भारत यात्रा के दौरान उनसे इन दोनों देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्धों तथा आपसी सहयोग के बारे में किस प्रकार की बातचीत हुई है;

(ख) क्या उन्होंने भारतीय इंजीनियरिंग सामान के लिये कुछ आर्डर बुक कराये हैं; और

(ग) यदि हां, तो ये आर्डर किन-किन फर्मों में बुक कराये गये और इनका मूल्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुण्डू) : (क) 8 मे 25 फरवरी, 1978 तक भारत की अपनी सद्भावना यात्रा के दौरान चीन के चार आयात/निर्यात निगमों के प्रतिनिधि मण्डल ने अपने मेजबान भारतीय पब्लिक क्षेत्र निगमों, निर्यात संवर्द्धन परिषदों,